भारत, चीन और बढ़ता फासला

अमर्त्य सेन

- **भारत के उलट चीन मानवीय जीवन में सुधार से होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में एशियाई आर्थिक विकास की सीख को ग्रहण करने से नहीं चूका**
- **बड़ा अंतर आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधानों में है**

आधुनिक भारत कई मायनों में सफल है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का उसका दावा खोखला नहीं है। भारत का मीडिया गतिशील और मुक्त है, किसी और राष्ट्र के लोगों के मुकाबले भारतीय हर दिन अधिक अखबार खरीदते हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद से जीवन प्रत्याशा 32वर्ष से बढ़कर 66 वर्ष यानि दुगुनी से भी अधिक हो गई है और प्रति व्यक्ति आय (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) पांच-गुना बढ़ी है। हाल के दशकों में किए गए सुधारों की बदौलत किसी समय कमजोर रही विकास दर लगभग 8 प्रतिशत वार्षिक तक पहुंच गई हालांकि पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें लगभग दो प्रतिशत तक की कमी हुई है। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले वर्षों तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही है और कम से कम एक प्रतिशत अंक से लगातार उसके पीछे रही ।

भारत किसी दिन आर्थिक विकास में चीन से आगे निकल जाएगा यह आशा काफी कम दिखती है। पर यह तुलना भारतीयों के लिए अधिक चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। इससे भी अधिक चिंता की बात आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में भारत और चीन के बीच के अंतर में है- एक ऐसा पहलू जो जीवन स्तर को संकुचित करता है और विकास को पीछे खींचता है।

दोनों देशों में काफी असमानताएं हैं लेकिन जीवन प्रत्याशा बढ़ाने, सामान्य शिक्षा का दायरा विस्तृत करने और अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने में चीन ने भारत से कहीं अधिक काम किया है। भारत में खास लोगों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराने वाले बहुत से विशिष्ट स्कूल हैं लेकिन सभी भारतीयों में से लगभग पांच में से एक पुरूष और तीन में से एक महिला अशिक्षित हैं और अधिकांश विद्यालय कम गुणवत्ता वाले हैं, आधे से भी कम बच्चे स्कूलों में चार साल तक पढ़ने के बावजूद 20 को पांच से भाग नहीं दे सकते।

आर्थिक विकास में भारत के किसी दिन चीन से आगे निकलने की आशा काफी कम दिखती है। भारत और चीन के बीच काफी बड़ा अंतर आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में है- एक ऐसा पहलू जो जीवन स्तर को संकुचित करता है और विकास को पीछे खींचता है।

हो सकता है कि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक हो लेकिन उसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली काफी अनियमित है-गरीबों को कम गुणवत्ता वाले और कई बार उनका शोषण करने वाले निजी चिकित्सालयों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास उपयुक्त मात्रा में सही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। चीन अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत स्वास्थ्य देखभाल पर व्यय करता है जबकि भारत केवल 1.2 प्रतिशत।

जीवन बेहतर बनाने में कमी

तथाकथित एशियाई आर्थिक विकास के उदाहणों से सीख ग्रहण करने की भारत की चूक में उसके प्रदर्शन की खामियों को तलाशा जा सकता है जिसके तहत मानवीय क्षमताओं में तीव्र विस्तार अपने आप में एक लक्ष्य और तीव्र विकास प्राप्त करने का अहम तत्व दोनों हैं। इस दृष्टिकोण को जापान ने काफी अच्छे से अपनाया। 1868 में मीजी पुनरुद्धार के दौरान उसने कुछ ही दशकों में पूर्ण शिक्षित समाज का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया। उस सुधार के अगुवा रहे किदो ताकायोशी ने इसे उल्लेखित करते हुए कहा, "हमारे नागरिक आज के अमेरिकियों अथवा यूरोपवासियों से किसी प्रकार अलग नहीं है। ये सिर्फ शिक्षित अथवा अशिक्षित होने का मामला है।" बाजार के साथ सरकारी गठजोड कर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में निवेश से जापान ने अपने जीवन स्तर और श्रम उत्पादकता को बढ़ाया है। जापान में युद्ध विभीषिका के दौर के बावजूद विकास के अनुभवों से प्राप्त सीख बरकरार रही और युद्ध के बाद की अवधि में दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और पूर्वी एशिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं ने इसका अनुसरण किया। माओ के समय में चीन ने भूमि सुधार और बुनियादी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में काम किया उसने 1980 की शुरूआत में बाजार सुधार पर ध्यान दिया। उसकी व्यापक सफलता ने विश्व अर्थव्यवस्था की शक्ल बदल दी। इन सीखों पर भारत ने अपर्याप्त ध्यान दिया है। क्या यह कोई पहेली है कि लोकतांत्रिक भारत ने चीन के मुकाबले अपने नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम ध्यान दिया? शायद, लेकिन यह कोई बहुत मुश्किल पहेली नहीं है। लोकतांत्रिक भागीदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून का शासन भारत में एक काफी हद तक एक वास्तविकता है और चीन में अभी भी काफी हद तक यह आकांक्षा मात्र है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कभी भुखमरी जैसे हालात पैदा नहीं हुए लेकिन चीन के दर्ज इतिहास में 1958 से 1961 के दौरान जब माओ के घातक ग्रेट लीप फॉरवार्ड (चीन द्वारा उसकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण का अभियान) की वजह से लगभग 30 मिलियन लोगों की जान गई। फिर भी - अल्पपोषण, असंगठित चिकित्सा प्रणाली अथवा कमजोर स्कूल प्रणाली जैसी भीतरी समस्याओं के लिए लोकतांत्रिक साधनों के इस्तेमाल के लिए सतत चर्चा, राजनीतिक भागीदारी, मीडिया कवरेज, लोगों के दबाव की आवश्यकता है। कम शब्दों में कहें तो अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया न कि कम।

सीखो/हासिल करो

चीन में शीर्ष स्तर पर फैसले लिए जाते हैं। भले ही उसके नेता बहुदलीय लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोधी न हो परंतु उसके प्रति आशंकित अवश्य हैं, लेकिन वे भूख, अशिक्षा और चिकित्सकीय असावधानी को दूर करने के लिए काफी प्रतिबद्ध हैं और यह उनका सबसे बड़ा श्रेय है।

आदेशात्मक लहजा

गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में आवश्यक सचेतता अनिवार्य होती है क्योंकि गलतियों को दुरुस्त कर पाना काफी मुश्किल होता है। किसी भी नियम के प्रति असहमति परेशानी का सबब बन सकती है। अन्याय के शिकार लोगों के लिए सहारे की उम्मीद कम होती है उदाहरण के लिए एक बच्चे की नीति काफी कठोर हो सकती है। लेकिन चीन के मौजूदा नेताओं ने मानवीय क्षमताओं को विस्तारित करने के मूलभूत नजरिए को काफी सक्षमता और कौशल से निभाया है।

भारत में असमानता को दूर करने का मामला केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है। भारत के उलट चीन, खासतौर पर सामाजिक-आर्थिक ढांचे के निम्नतम स्तर पर, मानवीय जीवन में सुधार से होने वाले आर्थिक लाभ के बारे में एशियाई आर्थिक विकास की सीख को ग्रहण करने से नहीं चूका। भारत

का विकास और निर्यात से पर्याप्त होने वाली इसकी आय सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि और विशेषीकृत ऑटो कलपुर्जों पर निर्भर होने लगी है जिसमें से अधिकांश संभ्रांत शिक्षित वर्ग के उच्च प्रशिक्षित कार्मिकों की भूमिका पर निर्भर है। तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के साथ लगभग सभी प्रकार के गैजेट तैयार करने की चीन की विनिर्माण क्षमता के अनुसार बनने के लिए भारत को समाज के हर स्तर पर बेहतर शिक्षित और स्वास्थ्यप्रद श्रमिक बल की आवश्यकता है। इसके लिए असमानता की प्रकृति और इसकी सीमा तथा आर्थिक विकास के साथ ही इसके नुकसानप्रद प्रभावों की जानकारी और इस पर सार्वजनिक चर्चा की जरूरत है।

(लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अमेरिका के हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय
में अर्थशास्त्र और दर्शन-शास्त्र के व्याख्याता हैं ।
साभार- द न्यूयॉर्क टाइम्स)